संख्या-25/1928/12-3-2014-100(2)/2013

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारी समितियां,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2014**

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सहकारिता विभाग की Construction of Godown at PACS योजना के लिए रू0-100200 हजार की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक-439/रा.कृ.वि.यो./लेखा-58/2014-15, दिनांक 12.8.2014 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-1034(2)/12-3-2014-100(2)/2013, दिनांक 7.5.2014 तथा शासनादेश संख्या-1662/12-3-2014-100(2)/2013, दिनांक 13.8.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग की Construction of Godown at PACS की परियोजना हेतु धनराशि रू0-100200 हजार (रू0 दस करोड़ दो लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को उक्त धनराशि दो समान किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त द्वितीय किश्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

5- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। आयुक्त/निबंधक, सहकारी समितियां द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

7- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए- 1-285/दस-2012- 10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्ाी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

9- उक्त धनराशि से प्रस्तावित गोदामों के निर्माण हेतु र्निविवादित भूमि की उपलब्धता एवं निर्माण कार्य की उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व आयुक्त/निबन्धक सहकारी समितियां तथा कार्यदायी संस्था पैक्फेड के प्रबन्ध निदेशक का होगा। स्वीकृत धनराशि से निर्मित किये जाने वाले गोदमों का निर्माण शासन द्वारा अनुमोदित डिजाइन/आगणन के

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार ही किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या-2520/12-3-2013-100(75)/2012, दिनांक 1.7.2013 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि आयुक्त/निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा नियमानुसार आहरित कर उक्त कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था, पैक्फेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- आयुक्त/निबंधक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

12- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्वयक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0306-सहकारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेग।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

सं**0-1928(1)/12-3-2014-**तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक, पैक्फेड, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।

12- वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13- निजी सचिव, मा. कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

14- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।

15- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http//:shasanadesh.up.nic.in